www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 29 | जौनपुर, सोमवार, 14 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पूर्व वायुसेना अधिकारी पर लोहे की रॉड से हमला, प्राथमिकी दर्ज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गुरुग्राम के 'मैग्नम ग्लोबल पार्क' में एक पार्किंग कर्मचारी ने कारगिल युद्ध में शामिल रहे एक सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन पर कथित तौर पर लोहे की 'रॉड' से हमला कर दिया, जिससे पूर्व सैन्य अधिकारी के सिर में गंभीर चोट आई और उनकी कोहनी की हड्डी टूट गई। पुलिस ने बताया कि पूर्व सैन्य अधिकारी अमित कुमार गुप्ता 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के 'ऑपरेशन सफेद सागर' दल का हिस्सा थे। गुप्ता ने आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार की घटना के बाद अस्पताल में तैयार की गई चिकित्सकीय–कानूनी (एमएलसी) रिपोर्ट गलत है और इसमें उनके सिर से खून बहने तथा कोहनी में लगी चोट का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही। पुलिस ने बताया कि सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन ने सेक्टर–65 थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार, यह मामला पार्किंग को लेकर हुए कथित विवाद से जुड़ा है। गुप्ता बृहस्पतिवार रात अपने परिवार के साथ रात्रिभोज के लिए मैग्नम ग्लोबल पार्क स्थित गोंजो रेस्तरां गए थे। गुप्ता ने बताया कि रात करीब आठ बजे वह अपने परिवार को रेस्तरां में छोड़कर कार खड़ी करने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पार्किंग कर्मचारियों ने उन्हें पहले 'वैले पार्किंग' स्थल (वह जगह जहां कर्मचारी वाहन लेकर उसे निर्धारित स्थान पर खड़ा करते हैं), फिर भूमिगत पार्किंग स्थल और उसके बाद बहुमंजिला पार्किंग की ओर भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि काफी देर तक उन्हें इधर–उधर भेजने के बाद कर्मचारियों ने उनकी कार खड़ी करने से इनकार कर दिया। इस कथित इनकार की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। शिकायत के मुताबिक, गुप्ता जब अपनी कार पीछे कर रहे थे, तभी एक पार्किंग कर्मचारी ने कार का अगला शीशा तोड़ने की कोशिश की। गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा, "जब मैं कार से बाहर निकला और इसका विरोध किया, तो कर्मचारी लोहे की 'रॉड' लेकर आया। उसने पहले मेरे हाथ और फिर सिर पर वार किया।

हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर हो नियमसंगत कार्रवाई - सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि सरकार हर पीड़ित की उचित समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता और शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने और जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री 'जनता दर्शन' में कुर्सियों पर बैठे हर पीड़ित के पास खुद चलकर गए। उनकी समस्याओं व शिकायतों को ध्यान से सुना। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि हर पीड़ित की उचित समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष कुछ पीड़ितों ने पुलिस से जुड़ी अलग–अलग शिकायतें बताईं। इस पर सीएम सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी ध्यान दें, किसी भी मामले में थाना, चौकी, बीट स्तर पर हीलाहवाली की शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी। हर मामले में दोषियों पर नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 'जनता दर्शन' में अभिभावकों के साथ आए नन्हे–मुन्नों का हालचाल जाना। उनकी पढ़ाई और उनकी रुचि के बारे में भी पूछा। सीएम ने बच्चों से कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ो और अन्य गतिविधियों (खेल, संगीत, कला आदि) में भी हिस्सा लो। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट देते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया।

महंगाई और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जूझ रहा है महाराष्ट्र, उद्धव का महाराष्ट्र सरकार पर तंज लगा

मुंबई, (एजेंसी)। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, शिवसेना नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सोमवार को महाराष्ट्र के बढ़ते सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक संकट के लिए सत्तारूढ़ महायुति सरकार की कड़ी आलोचना की। ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्र श्सामनाश में एक संपादकीय में राज्य की भयावह तस्वीर पेश की और दावा किया कि मुद्रास्फीति, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, कृषि संकट और बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ग्रस्त है। यह तर्क देते हुए कि वर्तमान शासक स्वयं महाराष्ट्र और राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा श्विघ्नश (बाधा) बन गए हैं। संपादकीय में त्योहारों के मौसम से पहले जनता की परेशानी बढ़ाने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की गई। चीनी, दूध, सीएनजी, घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि आम आदमी के त्योहारी बजट पर भले ही बुरा असर पड़ा हो, लेकिन भक्त भगवान गणेश का श्रद्धापूर्वक स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संपादकीय में पुणे के कार्यकर्ता विद्यानंद बापट पर हुए हालिया हमले का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने सार्वजनिक समारोहों के दौरान उच्च ध्वनि वाले डीजे सिस्टम का कड़ा विरोध किया था। संपादकीय में दावा किया गया कि ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के बजाय, सत्ताधारी दल ने कार्यकर्ता को शहरी नक्सल और बाहरी करार दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्णायक कार्रवाई के बजाय टालमटोल का रुख अपनाया। अल नीनो के गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए।

दिल्ली में 13800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की होगी शुरुआत – मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक सेवा कार्यकाल के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से महीने भर का सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत यमुना कायाकल्प के लिए 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं सहित कई विकास कार्यों की शुरुआत होगी। साथ ही अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आधिकारिक मंच भी लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत यमुना की सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेगी और अंगदान के लिए एक आधिकारिक मंच भी शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि महीने भर चलने वाला यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान 13,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं एवं योजनाओं का या तो उद्घाटन किया जाएगा या उनका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार 17 सितंबर को एक बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी, जिसमें 2,500 यूनिट रक्त एकत्र किया जाएगा। अभियान के तहत प्रस्तावित पहल की घोषणा करते हुए गुप्ता ने कहा, यमुना हमारे लिए आस्था का विषय है। यमुना की सफाई एक दिन की परियोजना नहीं है।

अमित शाह ने कहा कि अपनी सांस्कृतिक भाषा बोलने में किसी को हीन भावना नहीं रखनी चाहिए

नई दिल्ली, (एजेंसी)। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बोली जाने वाली अलग–अलग भाषाएं किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। अमित शाह ने कहा कि हर भाषा अपने साथ इतिहास, लोक परंपराएं और दुनिया को देखने का अलग नजरिया लेकर चलती है। ये सभी मिलकर नई पीढ़ी के मूल्यों को आकार देती हैं। उनके मुताबिक, भारत में मौजूद भाषाई विविधता ही देश की 'विविधता में एकता' की भावना को और मजबूत करती है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी का उद्देश्य दूसरी भारतीय भाषाओं से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। इसके बजाय हिंदी देश की अलग–अलग भाषाओं के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करती है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अलग–अलग मातृभाषाओं से जुड़े लोगों ने हिंदी को व्यापक संवाद की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से दुनिया की ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने, लेकिन अपनी मातृभाषा को न छोड़ने की अपील की। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों से अपनी मातृभाषा में बात करने को कहा। शाह ने कहा कि अपनी भाषा बोलने में किसी को हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भाषा हमें मां, मिट्टी, इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 'औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति' के आह्वान में भाषा की अहम भूमिका है। अमित शाह ने अपनी मातृभाषा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मातृभाषा गुजराती है। इसके बावजूद जब वह देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, तो आम लोगों से सीधे जुड़ने में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

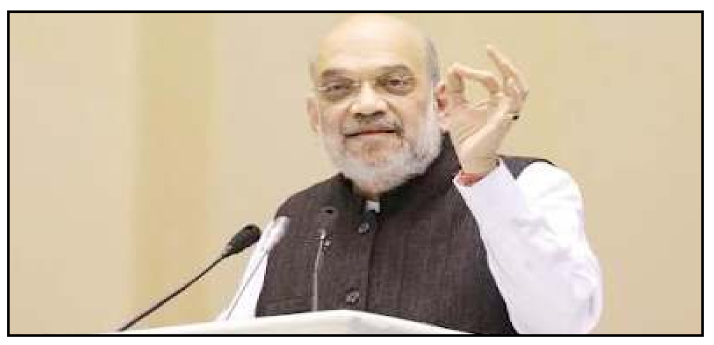

पैतृक सीट छोड़ भाजपा के गढ़ से लड़कर दिखाएं, किसे दी चुनौती - स्मृति ईरानी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में 2024 की हार, राहुल गांधी और कांग्रेस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हार–जीत राजनीति का हिस्सा है और जो लोग पैतृक या सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वहां से चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनकी कभी दाल नहीं गली। ईरानी ने भाजपा में महिलाओं की भूमिका, युवा राजनीति और अपने आगामी चुनाव को लेकर भी स्पष्ट जवाब दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि राजनीति को लेकर मेरा नजरिया थोड़ा अलग रहा है। ज्यादातर लोग राजनीति में सत्ता और पद पर बने रहने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के रूप में वर्षों विपक्ष का दौर देखा है। अमर उजाला डिजिटल के कार्यक्रम खरी बात में स्मृति ईरानी के साथ बातचीत के प्रश्न– आपने हाल ही में भाजपा संगठन में महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। 2024 के नतीजों के बाद आप अचानक टीवी सीरियल की दुनिया में वापस कैसे लौट गईं? उत्तर– पार्टी ने जब भी जो भी करने को कहा मैंने किया। कोई मूर्ख ही होगा जो कांग्रेस के गढ़ अमेठी में जाकर चुनाव लड़ने की सोचेगा, पार्टी ने मुझे वहां भेजा और मैंने चुनाव लड़ा। जहां तक टीवी पर लौटने की बात है तो मैंने करीब बीस साल टीवी का शिखर देखा, अपनी मेहनत से कमाने में कोई हर्ज नहीं है। यशवंत राव केलकर जी कहते थे कि सफलता के शिखर को छोड़कर राजनीति में आकर देश को कुछ देना चाहिए, मैंने उनके इस कथन को आत्मसात किया। आप जब अपनी पुरानी टीवी सीरियल की दुनिया में रम गईं तब क्या आपको उम्मीद थी कि पार्टी दोबारा आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी? उत्तर– पार्टी ने मुझे छोड़ा कहां था जो मेरी उम्मीद टूटती, मैं लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती रही।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो, 'दिल जीतने वाले' अंदाज के कायल हुए पीएम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की सकारात्मकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद आती है। ब्रिक्स समिट के दूसरे और अंतिम दिन पीएम मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इनमें सुबियांतो भी थे जिन्होंने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ उनका अभिवादन किया। पीएम ने इस मुलाकात को बेहद खास बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "ब्रिक्स दिल्ली समिट के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका अपनापन, पॉजिटिविटी और आशावादी रवैया हमेशा दिल जीत लेता है।" प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत और इंडोनेशिया कई सेक्टर में अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करते रहेंगे। दोनों के बीच काफी आत्मीय रिश्ते हैं। नई दिल्ली को मिलाकर 2026 में दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच मुलाकात हुई। पहली मुलाकात जकार्ता में और दूसरी नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर जकार्ता गए थे। इस दौरान राष्ट्रपति भवन 'इस्ताना मर्देका' में दोनों नेताओं के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंटांग आदिपूर्णा' से सम्मानित किया गया था। दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर चर्चा की थी। वहीं, एक सामुदायिक कार्यक्रम में सुबियांतो ने खुद को पीएम मोदी का फैन बताया था।

भारत की संस्कृति छिपाई जा रही – राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के लिए आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज का मेन्यू अब सियासी बहस का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत मंडपम में आयोजित डिनर में मेहमानों को पारंपरिक भारतीय शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर देश की विविध खान–पान संस्कृति को छिपाने और अपनी पसंद मेहमानों पर थोपने का आरोप लगायालोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि करीब 80 फीसदी भारतीय मांसाहारी हैं और भारतीय मांसाहारी भोजन की अपनी अलग पहचान है। इसी के साथ उन्होंने छोले–भटूरे की तस्वीर साझा करते हुए अपने अंदाज में टिप्पणी की। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की खान–पान संबंधी पसंद थोपने की आदत अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने इसे भारत की बहु–व्यंजन संस्कृति से जोड़कर सवाल खड़े किए।कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि कांग्रेस ठत्प्ेै देशों के नेताओं को परोसे गए भोजन के मेन्यू पर भी राजनीति कर रही है। रिजिजू के मुताबिक मेहमानों को स्वाद और पोषण से भरपूर भारतीय शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों की खान–पान परंपराओं को शामिल किया गया था।मिठाई में पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और शहतूत फिरनी शामिल रही। इस मेन्यू के जरिए अलग–अलग क्षेत्रों की भारतीय पाक परंपराओं को सामने रखने की कोशिश की गई।खान–पान को लेकर यह बहस बंगाल में हुई एक हालिया राजनीतिक–सामाजिक चर्चा के बाद और तेज हुई। बागेश्वर पीठ के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हावड़ा में दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास मांसाहार को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद बंगाल की मछली खाने की परंपरा को लेकर विवाद खड़ा हुआ और कांग्रेस ने उनके पोस्टर जलाकर विरोध जताया।

मेदांता में जिंदगी की जंग लड़ रही बेटी,न्याय के लिए पुलिस व जनता दरबार तक भटक रही मां

आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर,कार्रवाई में देरी पर उठ रहे गंभीर सवाल

ब्यूरोचीफ दीपक श्रीवास्तव

लखनऊ।एक मां की बेटी मेदांता अस्पताल लखनऊ के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाने से लेकर मुख्यमंत्री दरबार तक फरियाद लेकर चक्कर लगा रही है।मामला थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का है,जहां 21 वर्षीय युवती के साथ कथित मारपीट, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।पीड़िता की मां रतना का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ उसके कथित बॉयफ्रेंड प्रियांशु गुप्ता निवासी लाला टेरी, बझरिया, शाहजहांपुर द्वारा लंबे समय से प्रताड़ना और मारपीट की जा रही थी।आरोप है कि 31 अगस्त को लखनऊ में हुई एक गंभीर घटना के बाद बेटी की हालत बिगड़ गई,जिसके बाद उसे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया।मां के मुताबिक,बेटी अभी भी गंभीर हालत में उपचार चल रहा है।देखा जाये तो शिकायत लेकर थाने से सीएम दरबार तक पहुंची मां रतना का कहना है कि उसने स्थानीय थाना सुशांत गोल्फ सिटी में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।इसके बाद वह अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई दरबार तक भी पहुंची,लेकिन आरोप है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी अथवा मामले में अपेक्षित प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद मामला कार्रवाई के इंतजार में अटका हुआ है और आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।पीड़िता की मां ने दावा किया है कि उसके पास मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।इनमें बेटी को कथित रूप से कमरे में बंद कर डराने–धमकाने की वीडियो रिकॉर्डिंग, कथित प्रताड़ना से संबंधित वीडियो, गाली–गलौज एवं अभद्र भाषा की कॉल रिकॉर्डिंग,सीसीटीवी फुटेज तथा अस्पताल में उपचार और चोटों से संबंधित मेडिकल दस्तावेज शामिल हैं।पीडिता मां की मांग है कि इन सभी साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित कराते हुए निष्पक्ष जांच का हिस्सा बनाया जाए, ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके।पुलिस कर्मियों पर भी लगाए गंभीर आरोप पीड़िता रतना ने कुछ पुलिसकर्मियों पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाया है।उसने विशेष रूप से पुलिस कर्मी सूरज सिंह और अरविंद यादव का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनके स्तर से मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पुलिस कर्मियों का पक्ष सामने आना बाकी है।पीड़िता का कहना है कि आरोपी की ओर से उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका भी बनी हुई है।ऐसे में उसने परिवार और बेटी की सुरक्षा की भी मांग की है।पीड़िता की मां का कहना है कि सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं और अभियान चला रही है।ऐसे में यदि किसी गंभीर शिकायत पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।पीडिता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित कराने,आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई तथा पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं।एक तरफ अस्पताल में बेटी जिंदगी की जंग लड़ रही है,दूसरी तरफ मां इंसाफ की लड़ाई।अब देखना यह है कि उसकी फरियाद पुलिस और शासन के दरवाजे से कब न्याय के दरवाजे तक पहुंचती है।

संपादकीय

आर्थिक कदम भी दंत–विहीन

सैन्य विकल्प समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका अब आर्थिक दबाव के जरिए वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो सैन्य बल से संभव नहीं हुआ। लेकिन आर्थिक कदम भी दंत–विहीन ही हैं। अमेरिका ने ईरान को दुनिया में पराया बना देने के बड़े इरादे के साथ श्ऑपरेशन इकॉनमिक आउटकास्टश्का एलान किया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि अब ईरान से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध रखने वाले देश और कंपनियों को डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जब प्रतिबंधों की सूची जारी की गई, तो ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका सचमुच अपने एलान को हकीकत में बदलने में सक्षम है। इसमें भारत की चार कंपनियों सहित लगभग 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों को शामिल किया गया, लेकिन चीन की किसी वित्तीय संस्था को निशाना नहीं बनाया गया। इस बारे में पूछने पर बेसेंट ने कहा– वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मैं क्यों उड़ा डालना चाहूंगा? मतलब साफ है। अमेरिका की राय है कि चीनी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने से पूरी वित्तीय प्रणाली संकटग्रस्त हो सकती है। जबकि चीन ही ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। वह ईरान में बड़ा निवेशक भी है। अतरू चीन को रोके बिना अमेरिकी प्रतिबंध दिखावटी दांत बन कर रह जाएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताजा अमेरिकी प्रतिबंध को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर है। उसने कहा कि चीन अपने हितों की मजबूती से रक्षा करेगा। तो फिर अमेरिकी प्रतिबंध से कौन प्रभावित होगा? रूस पहले से ही सबसे अत्यधिक प्रतिबंधित देश है, इसलिए उस पर नई पाबंदियों का नगण्य असर होना है। दरअसल, प्रतिबंधों की घोषणा के बाद रूस ने ईरान से 25 बिलियन डॉलर का परमाणु समझौता करने का एलान कर दिया। ऐसे में स्पष्ट है कि अमेरिकी कदम का दबाव सिर्फ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकाः इजराइल के कुछ सहयोगी देश ही महसूस करेंगे, जो ईरान के लिए किसी गंभीर चिंता का विषय नहीं है। इसीलिए विश्लेषकों ने राय जताई है कि ऑपरेशन इकॉनमिक आउटकास्ट असल में यह स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका के पास सैन्य विकल्प समाप्त हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका अब आर्थिक दबाव के जरिए वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो सैन्य बल से संभव नहीं हुआ। लेकिन आर्थिक कदम भी दंत–विहीन ही हैं।

भारत-चीन शिखर वार्ता से व्यापार बढ़ाने के मौके खुलेंगे

विवेक

ऐसे समय में जब वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला अस्थिर हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विकासशील देशों को पहले से कहीं ज़्यादा एक ऐसे सहयोग मंच की जरूरत है जो व्यावहारिक समाधान दे सके और साझा विकास को बढ़ावा दे सके। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स सहयोग तंत्र से नई उम्मीदें जगी हैं। ब्रिक्स के दो मुख्य सदस्य होने के नाते, चीन और भारत, को बहुत उम्मीदें हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं और 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर काफी उम्मीदें हैं। 2025–26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 18.31 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 151.1 अरब तक पहुंच गया है। हालांकि, नई दिल्ली में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 112.16 अरब के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कुछ चिंता भी है। चीन के विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस चिंता पर ध्यान दिया है और कुछ खास क्षेत्रों में चीन के साथ जुड़कर भारत को मौजूदा भू–राजनीतिक उथल–पुथल के बीच वैश्विक व्यापार में कुछ अतिरिक्त फायदे दिलाने की कोशिश की जा रही है।जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जब वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला अस्थिर हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विकासशील देशों को पहले से कहीं ज़्यादा एक ऐसे सहयोग मंच की जरूरत है जो व्यावहारिक समाधान दे सके और साझा विकास को बढ़ावा दे सके। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिक्स सहयोग तंत्र से नई उम्मीदें जगी हैं। ब्रिक्स के दो मुख्य सदस्य होने के नाते, चीन और भारत, को बहुत उम्मीदें हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं और उनके औद्योगिक ढांचे अलग–अलग हैं, और उनका आपसी आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक सहयोग व्यापक ब्रिक्स प्रगति का एक अहम हिस्सा है।चीन के विदेश व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत–चीन व्यापार में हालिया तेजी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही औद्योगिक पूरकता का स्वाभाविक नतीजा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से चीनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उत्पादों, एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स और औद्योगिक पुर्जों की लगातार मांग पैदा हुई है।साथ ही, भारत के कृषि उत्पादों, खनिज संसाधनों और खास उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी चीनी बाजार में काफी गुंजाइश है। सप्लाई और मांग की इस दोतरफा आवाजाही ने व्यापार के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे साबित होता है कि चीन–भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग एक ठोस और यथार्थवादी आधार पर टिका है। चीनी सरकार के आधिकारिक मुखपत्र श्ग्लोबल टाइम्सश के ताजा अंक के अनुसार, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। हाल के वर्षों में, भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स (बीच के सामान) के लिए ज़्यादा स्थिर आपूर्ति श्रृंखला और कम लागत वाली सीमा के आर–पार की व्यापार सुविधाएं न केवल व्यापार के आंकड़ों को बढ़ाएंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ज़्यादा नौकरियां और बेहतर औद्योगिक श्रृंखला क्षमता भी लाएंगी। इसलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले चीन का सुझाव है कि अगर भारत इस इसका इस्तेमाल चीन–भारत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने के मौके के तौर पर करता है, तो यह उसके अपने विकास की जरूरतों के हिसाब से एक बहुत ही व्यावहारिक और पूरी तरह से तर्कसंगत फैसला होगा। इससे भी अहम बात यह है कि ऐसा कदम ब्रिक्स सहयोग में भारत का एक बड़ा योगदान होगा। ग्लोबल टाइम्स (जीटी) का विश्लेषण बताता है कि कुछ लोगों को यह चिंता हो सकती है कि चीन के साथ गहरे आर्थिक संबंध भारत के व्यापार घाटे को बढ़ा सकते हैं या कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता पैदा कर सकते हैं। हालांकि ऐसी चिंताएं समझ में आती हैं, लेकिन उनसे निपटने का सही तरीका रुकावटें खड़ी करना नहीं है– बल्कि सहयोग बढ़ने के साथ–साथ जरूरी संरचनात्मक बदलाव करना है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन और भारत के बीच व्यापार घाटे की समस्या विकास के साथ–साथ धीरे–धीरे पैदा हुई है, और इसका समाधान भी अंततरू और मजबूत विकास से ही निकलेगा। चीनी अधिकारियों का कहना है कि भारत अपने प्रतिस्पर्धी सामान और सेवाओं के लिए चीन के बाजार तक पहुंच बना सकता है, साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए उचित अंतरिम सुरक्षा उपाय भी लागू कर सकता है। सहयोग का मतलब सि+र्फ एक तरफ से दरवाजे खोलना नहीं है – बल्कि स्मार्ट और आपसी फायदे वाले संबंध बनाना है। दोनों देशों के पास जोखिमों को संभालने और मोटे तौर पर संतुलित नतीजे सुनिश्चित करने के लिए काफी आर्थिक ताकत्त और नीतिगत गुंजाइश है। जीटी के अनुसार, आज के जटिल और अस्थिर वैश्विक माहौल में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक साझा लक्ष्य हैरू अपने उद्योगीकरण और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना। ब्रिक्स मंच इस लक्ष्य को हासिल करने का एक अहम जरिया है। जब चीन और भारत– जो उभरते बाजार की दो बड़ी ताकतें हैं– एक–दूसरे के करीब आते हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं और ब्रिक्स तंत्र के जरिए आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करते हैं, तो इसके फायदे दोनों देशों की कंपनियों और लोगों से कहीं आगे तक पहुंचेंगे। इससे ब्रिक्स की एकजुटता भी मजबूत होगी, जिससे यह समूह व्यापक विकासशील दुनिया के सामने मौजूद विकास की चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान देना जारी रख सकेगा।

आंकड़ों से छिप नहीं सकता भरोसे का संकट

मोहन

तकनीकी जानकारी जीडीपी के आंकड़ों को समझा सकती है जबकि अनुभव पर आधारित समझ उन आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल उठा सकती है। वहीं, व्यावहारिक समझ उन्हें बेकार बताकर खारिज कर सकती है– खासकर ऐसी दुनिया में जहां वास्तविक जिंदगी का अनुभव बताए गए आंकड़ों से कोसों दूर है। जब सरकारी बयानों में बताई गई बातें लोगों की असल जिंदगी से मेल नहीं खातीं तो लोगों की जिंदगी की सच बन जाती है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, धीमी है या बहुत सुस्त है? इस बात पर जोरदार बहस चल रही है कि क्या 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सरकार के दावे के मुताबिक सचमुच 7.8 प्रतिशत थी या सिर्फ 2.6 फीसदी, जो पिछले साल के आंकड़ों में बदलाव और महंगाई के असर (इन्फ्लेशन डिफ्लेटर) को ठीक से जोड़ने पर लगभग शून्य हो जाता है। इस बहस का फैसला सिर्फ 'आंकड़ों' से नहीं हो सकता। दक्षिण–एशियाई और प्रवासी तकनीकी जानकारी जीडीपी के आंकड़ों को समझा सकती है जबकि अनुभव पर आधारित समझ उन आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल उठा सकती है। वहीं, व्यावहारिक समझ उन्हें बेकार बताकर खारिज कर सकती है– खासकर ऐसी दुनिया में जहां वास्तविक जिंदगी का अनुभव बताए गए आंकड़ों से कोसों दूर है। जब सरकारी बयानों में बताई गई बातें लोगों की असल जिंदगी से मेल नहीं खातीं तो लोगों की जिंदगी की सच बन जाती है और सरकारी बयान सिर्फ एक कहानी या नैरेटिव बनकर रह जाते हैं। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर हो रही बहस मौजूदा हालात की निशानी है। ये उस भरोसे के संकट को दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व नौकरशाहों ने आंकड़ों को लेकर सरकार से मोर्चा ले लिया है। इससे इस मामले ने एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप धर लिया है तथा श्दवांश और भी ऊंचे हो गए हैं। पिछले सप्ताहांत पीएम ने विकास की कहानी को इन शब्दों में पेश किया–श्पश्चिम एशिया में युद्ध और वैश्विक व्यापार की बाधाओं के बीच 7.8 प्रतिशत की तिमाही विकास दर हासिल करना भारत की आंतरिक क्षमता को दर्शाता है। जोरदार सरकारी दावों और उनके तीखे जवाबों ने इसे सरकार के लिए एक राजनीतिक दलदल बना दिया है जो पहले से ही मुश्किल हालात का सामना कर रही है। असल में जंतर–मंतर पर हुए विरोध–प्रदर्शनों के बाद 7.8 प्रतिशत की विकास दर सरकार के लिए पहली अच्छी खबर थी क्योंकि इन प्रदर्शनों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और जुलाई में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। इस विवाद में सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। प्रदर्शनों के दौरान एक ऐसे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया और उन पर मीम्स बनाए गए जिन्हें कभी बहुत ताकतवर और अजेय माना जाता था। विरोध–प्रदर्शनों को संभालने के तरीके को लेकर उनके गृह मंत्री अमित शाह को कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। अंदरूनी स्तर पर भारी तनाव की बात कहने वाले एक पूर्व नौकरशाह को जिस तरह से नई दिल्ली में घंटों तक हिरासत में रखा गया उससे इस बात को और बल मिला है कि अंदर कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। एक समय था जब मोदी की कही लगभग कोई भी बात गलत नहीं मानी जाती थी। अब एक ऐसा समय आ गया है जब उनकी कही लगभग कोई भी बात सही नहीं मानी जाती। इस बात पर गौर करें– 2014 में केन्द्र में सत्ता में आने से ठीक पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने मुंबई में उद्योगपतियों के एक समूह से खुलकर कहा था कि उन्हें पता है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली जिस बुलेट ट्रेन का सपना वे देख रहे थे, उसमें कोई सवारी नहीं करेगा। लेकिन जल्द ही प्रधानमंत्री बनने वाले उसी व्यक्ति ने कहा कि, श्हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि हमारे पास बुलेट ट्रेन है।श चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि चीनी लोग भी पूरे देश के बजाय सिर्फ शंघाई को ही दुनिया के सामने पेश करते हैं। दर्शकों ने तालियां बजाईं। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। गहराई से देखें तो यही वह सोच या कार्य–पद्धति है जो सरकार के साथ लगातार बनी रही है और नैरेटिव बनाए रखने के लिए कई विचारों, फैसलों और अनुमानों को आकार देती रही है। दुनिया को जो दिखाना है उसे पहले देश के भीतर दिखाना और पेश करना जरूरी है। भारत की जीडीपी की कहानी इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार के बेहतर प्रदर्शन के दावों पर लोगों का भरोसा और विश्वास कम हुआ है। गैर–निष्पादित परिसंपत्तिय (नॉन–परफॉर्मिंग एसेट्स) को साफ करने के दावे और सिस्टम के असल कामकाज को लेकर फिर से उठे विवाद पर गौर करें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के हालिया आदेश से एक समाधान निकाला गया जिसमें टीवी के एक पूर्व दिग्गज को कुल 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये चुकाने थे। ये दावे एलआईसी हाउसिंग

फाइनेंस लिमिटेड ने ट्रिब्यूनल के सामने रखे थे। यानी हर सौ रुपये के कर्ज के बदले तीन पैसे से भी कम। उस दिग्गज का कहना है कि वे लगभग कंगाल हो चुके हैं। श्समझौतेश् का यह चौंकाने वाला मामला अब रोक दिया गया है। इसके अलावा, उस दिग्गज के खिलाफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। कोई एक मामला भले ही अहम हो लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी वह बात है जिसकी ओर वह इशारा करता है। वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2025 के बीच सरकारी बैंकों का कुल एनपीए 8.96 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2.84 लाख करोड़ रुपये हो गया पर बही–खातों से यह बैड स्टॉक (खराब लोन) कैसे हटाया गया? यह रिकवरी के बजाय श्राइट–ऑफश (बट्टे खाते में डालने) के जरिए किया गया। उन्हीं आठ सालों में, 6.72 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी और अपग्रेडेशन के मुकाबले 10.76 लाख करोड़ रुपये राइट–ऑफ किए गए जिसका अनुपात 1.60 था। हर एक रुपये की रिकवरी के बदले 1.60 रुपये राइट–ऑफ किए गए। 2025 के लिए सरकारी बैंकों द्वारा राइट–ऑफ की गई रकम रिकवरी से लगभग दोगुनी थी। इस सबके बारे में आधिकारिक जवाब यह है कि राइट–ऑफ एक अकाउंटिंग एंट्री है न कि लोन माफी, मतलब उधार लेने वाला व्यक्ति अभी भी लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार रहता है। वास्तव में रिकवरी कम ही रहती है। यह हमें श्तकनीकी रूप से सही होनेश् और श्जमीनी हकीकतश् के उस अंतर की समस्या पर वापस ले जाता है ।

त्योहार से पहले धार्मिक उन्माद

शारदीय नवरात्रि कुछ ही समय में आने वाली है, और धर्मोन्मादियों ने अभी से आस्था, भक्ति, उमंग और उत्साह के इन दिनों पर तनाव की काली छाया डाल दी है। मां दुर्गा के नौ रूपों और उनकी शक्ति का यह पर्व देश के पूर्वी हिस्से में अलग तरीके से मनाया जाता है और पश्चिमी हिस्से में अलग तरीके से। प.बंगाल के दुर्गा पंडालों से लेकर गुजरात में शक्ति की आराधना के लिए किए जाने वाले गरबा नृत्य हर किसी की अलग खासियत है। भारत की विविधिताओं में एकता वाले फलसफे में एक फलसफा यह भी है कि एक ही धार्मिक पर्व को कितने अलग–अलग तरीकों से, अलग–अलग राज्यों में मनाया जाता है। अब तो महानगरों में जहां नौकरी, कारोबार आदि के सिलसिले में सारे देश से आए लोग रहते हैं, वहां एक जगह पर बंगाल के तरीके की दुर्गापूजा मनाई जाती है और दूसरी जगह पर गुजरात का गरबा होता है। हिंदुस्तान की ऐसी ही खूबसूरती दुनिया में प्रसिद्ध है। मगर भाजपा की मोदी सरकार आने के बाद इस खूबसूरती पर कालिमा छा रही है।मानसिक स्ध्वास्ध्थ्ध्य म्ततवत सवंकपदह 'के. अभी रविवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुओं से दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहार से बचने की अपील की और कहा कि उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि दुर्गा पूजा और उससे जुड़े आयोजनों के दौरान मांसाहारी भोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोलकाता के हिंदुओं को इस मुद्दे पर जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो पूजा के दौरान मांसाहार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा के समय देवी प्रतिमा के आसपास मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। गनीमत यह रही कि धीरेंद्र शास्त्री के ऐसे बेतुके बयान पर न केवल विपक्षी तृणमूल कांग्रेस बल्कि खुद सत्ता में बैठी भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई है। टीएमसी प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा बंगालियों के लिए केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और भावनाओं का हिस्सा है। दत्ता ने कहा कि बंगाली समाज अपनी श्मां दुर्गाश का उत्सव किस तरह मनाएगा, यह कोई बाहरी व्यक्ति तय नहीं कर सकता। रिजु दत्ता ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल बंगालियों को यह बताने की कोशिश करेगा कि उन्हें अपनी परंपराओं के अनुसार कैसे पूजा करनी चाहिए, तो वह श्आग से खेल रहा होगा।श रिजु दत्ता ने आरोप लगाए कि भाजपा बंगालियों की थाली से मछली और मांस हटाना चाहती है। इसके लिए पूजा से पहले कई रेस्तरां पर कार्रवाई की जा रही है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो फिर तय है कि प.बंगाल में भाजपा टिक नहीं पाएगी। क्योंकि इसमें सीधे बंगाली अस्मिता पर चोट की जा रही है। वैसे धीरेंद्र शास्त्री की अपील पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी दो टूक जवाब दिया है कि किसी धार्मिक व्यक्ति या राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है कि वह बंगाल के लोगों को बताए कि उन्हें क्या खाना या पहनना चाहिए। भट्टाचार्य ने कहा, श्बंगालियों को अपने तरीके से जीने दें। बंगाली वही खाएंगे जो वे खाते आए हैं।श्र उन्होंने सवाल किया कि क्या बंगाली मछली और मांस नहीं खा सकते? इस संदर्भ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी उल्लेख किया और कहा कि उनके विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी संत को शाकाहार का प्रचार करने का अधिकार है और ऐसा करना अपराध या पाप नहीं है। लेकिन श्पाखंडश्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। भट्टाचार्य के मुताबिक, धार्मिक व्यक्ति की निजी राय को बंगाली समाज के लिए नियम नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह मोदी सरकार के करीबी अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने भी धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना सोशल मीडिया पर लिखा कि शाक्त हिंदू धर्म में मांस का महत्वपूर्ण स्थान है और प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों में इसे मां दुर्गा और मां काली को अर्पित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा की नवमीध्दशमी पर श्रद्धालुओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला प्रसाद कई परंपराओं में मांस होता है और इस धार्मिक परंपरा में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म भाजपा के वरिष्ठ नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने तो यहां तक कहा कि वह स्वयं नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन करते हैं और फिर भी ष्100 प्रतिशत हिंदूष् हैं। तथागत रॉय ने कहा कि हिंदुत्व में किसी एक तरह की जीवनशैली सब पर थोपने की परंपरा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है और कोई भी व्यक्ति उनके जीवन को आदेश देकर नियंत्रित नहीं कर सकता। दक्षिण–एशियाई और प्रवासी ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि भाजपा के लोगों की धार्मिक भावनाएं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से आहत हुई हैं। चूंकि मामला एक ही परिवार का है, इसलिए भाजपा इसे किसी तरह संभाल लेगी। लेकिन अब कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि जब इसी तरह मुसलमानों या ईसाइयों के धार्मिक पर्वों में दखलंदाजी की जाती है, जिससे उन्हें खुशियां भी डर–डर कर मनानी पड़ती हैं, तब उन्हें कैसा लगता होगा।

सत्ता चौबीसों घंटे चलते रंगमंच में बदल गई

हरिशंकर व्यास

तो अगले एक महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे–मोहरे का अखिल भारतीय प्रोपेगेंडा होगा। हां, सप्ताह में खबर थी कि मोदी ने भाजपा संगठन, नेताओं, मंत्रियों को सात सितंबर से सात अक्टूबर के बीच पच्चीस साला मोदी पावर की इवेंट के कार्यक्रमों का खाका बनवाया है। मतलब मोदी का जन्मदिन (17 सितंबर) उत्सव, सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा, रक्तदान शिविर, मोदी के कामों पर सेमिनार और व्याख्यान आदि–आदि। इसी के लिए दिल्ली में ब्रिक्स बैठक का आयोजन भी है। रूस के पुतिन, चीन के शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सहित 21 देशों के नेताओं को भारत ने न्योता दिया है। ये आएंगे भी क्योंकि जब दुनिया पुतिन, मसूद पेजेशकियान के गले लगने को तैयार नहीं तो दिल्ली में लालकालीन स्वागत, फोटोशूट का मौका कोई क्यों चूके। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान जाएंगे और उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। ध्यान रहे इन दोनों संगठनों को पश्चिमी देश, अमेरिका चीन का हितधारक मानते हैं। नवंबर में जी–20 की अमेरिका मेजबानी करेगा और डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ब्रिक्स के खिलाफ बोलते रहते हैं। पर मोदी के लिए विश्व राजनीति की दिशा–दशा, भारत, उसकी विदेश नीति के दीर्घकालीन हितों का कोई अर्थ नहीं है। उनका मात्र उद्देश्य दुनिया के नेताओं से गले लगने, लगाने और ट्रंप–शी जिनपिंग, पुतिन आदि के साथ फोटो खिंचाने का होता है ताकि भक्त हिंदू उन्हें विश्व नेता की तरह पूजते रहें। और समय–असवर क्योंकि 25 साला सत्ता का धूमधड़ाका बनाने का है तो विश्व नेताओं के साथ फोटोशूट तो सोने में सुहागा है। सोचें, मोदी से पहले 1947 से 2014 तक के हर प्रधानमंत्री पर? क्या नेहरू, वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह किसी ने भी जनता को उल्लू बनाने के लिए ऐसा कोई तमाशा किया कि वे इतने–इतने साल सत्ता में रहे तो कांग्रेस या भाजपा और सरकार उनकी महिमा में सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा, सेमिनार और व्याख्यान आयोजित करें! कैबिनेट के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री की आरती उतारें, उनका प्रोपेगेंडा करें! तो मोदी ऐसा क्यों करते हैं? बकौल लालकृष्ण आडवाणी (अप्रैल 2014)– मैं नरेंद्र भाई को अपना चेला नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उनसे अधिक प्रतिभाशाली और कुशल इवेंट मैनेजर कभी नहीं देखा। भक्त मूर्ख जन भले न मानें लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता के 25 साल (13 साल सीएम–12 साल पीएम) में एक–एक साल का, एक–एक महीने की सुर्खियों का हिसाब लगाएं तो 9,130 दिनों में लोगों को बहकाने, भाषण देने, झांकियां दिखाने, नए–नए वादे करने, इवेंट आयोजित करने का मोदी रिकॉर्ड ही निकलेगा। हां, नरेंद्र मोदी ने भारत को सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक इवेंट–ग्राउंड बनाया है। और मंच कभी खाली नहीं रहता। आज शिलान्यास, कल उद्घाटनय आज संकल्प, कल गारंटीय आज अमृतकाल, कल विकसित भारत। एक पर्दा गिरने से पहले दूसरा उठ जाता है। जनता को हिसाब लगाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, उसके आगे अगली झांकी आ जाती है। उस नाते नरेंद्र मोदी वह राजनीतिक केस स्टडी हैं, जिसमें सत्ता चौबीसों घंटे चलते रंगमंच में बदल गई। हर कुछ सप्ताह में नया सेट, नया नारा, नई झांकी, नया संकल्प और नया भविष्य केवल नायक स्थायी। दर्शक पिछले दृश्य का हिसाब पूछें, उससे पहले अगला पर्दा उठ चुका होता है। और इस तथ्य को नोट करें कि नरेंद्र मोदी का गुजरात का मुख्यमंत्री दफ्तर हो या दिल्ली का प्रधानमंत्री दफ्तर, वह केवल और केवल नौकरशाहों–अफसरों से चलता आया है। नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, या नरसिंह राव, डॉ. मनमोहन सिंह की सत्ता इनके स्वयं के लिखाए नोट, लिखित निर्देशों, विचारों मतलब प्रधानमंत्री के निज दिमाग से चलती थी। नेहरू के 17 वर्षों के कार्यकाल में दफ्तर हो या तीन मूर्ति आवास, दर्जनों स्टेनोग्राफर होते थे। फाइल आती, निर्देश होता तो खुद फाइल पर लिखते या स्टेनोग्राफर से नोट बनवा कर कैबिनेट सचिवों, मंत्रियों, सचिवों को भेजते। और उनके कार्यकाल के आर्काइव की फाइलें इसका प्रमाण हैं। शास्त्री ने एलके झा को अपने प्रधानमंत्री सचिवालय में रखा लेकिन वे स्वयं अंग्रेजी–हिंदी ड्राफ्ट देखते और सरकार चलाते थे। नरेंद्र मोदी ठीक विपरीत हैं। उनके सीएमओ, पीएमओ के पच्चीस सालों की फाइलें जब आर्काइव में पहुंचेंगी तो उनका राज वैसा ही निकलेगा जैसा बिहार में राबड़ी देवी का था। ध्यान रहे देश के दूसरे बड़े प्रांत बिहार में राबड़ी देवी का साढ़े सात साल शासन रहा। वे भी अफसरों के बनाए नोट, फाइलों, कैबिनेट बैठकों के एजेंडा (राज्यों में मुख्य सचिव और दिल्ली में कैबिनेट सचिव) की उस सत्ता से चलती थीं, जैसे नरेंद्र मोदी चलते हैं। राबड़ी देवी को सलाह देने वाली अधिकारी राजबाला वर्मा हुआ करतीं। वे नोट बनातीं थीं, फाइल प्रोसेस करती थीं, मुख्यमंत्री के दस्तखत की जगह लाइन खींच देती थीं और उस जगह राबड़ी देवी जैसे–तैसे दस्तखत करती थीं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के गांधीनगर सीएमओ में 2001 में उनके प्रमुख सचिव डॉ. पीके मिश्रा थे तो वे आज भी प्रधानमंत्री दफ्तर में उनके प्रमुख सचिव हैं। जैसे लालू–राबड़ी या नीतीश कुमार के 1990 से 2025 तक 35 वर्षों के चंद अफसरों से बिहार की दशा–दिशा, नियति बनी, वही मोदी के 25 साला गुजरात–भारत की दशा–दिशा और सेहत का समय है। यह रियलिटी भारत की मंडल, कमंडल राजनीति में हिंदुओं की उस दशा को जाहिर करती है, जिसका डीएनए है श्कोऊ नृप होउ हमहि का हानीश्र या जो सत्तावान है वही हुक्म है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं! इसमें नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत की राजनीति में मील के पत्थर हैं। क्योंकि उन्होंने अफसरों को शासन का कोर बना कर सरकार याकि प्रधानमंत्री के पद को ऐसा रंगमंच बनाया है, जिसमें अभिनेता एक ही है और वह हर महीने, हर दिन नया सेट, नया संवाद, नया उद्घाटन, नई झांकी से भक्तों को रिझाता रहता है। उनके शासन का भाषण, घोषणा अगली घोषणा तक जीवित रहती है, फिर नया पर्दा उठता है और पिछला दृश्य, दिखाया सपना यादगार से आउट हो जाता है। उनकी राजनीति मदारी, जादूगर जैसी नहीं, बल्कि एक आधुनिक स्टूडियो जैसी है। कब गले लगेंगे, रोशनी कहां पड़ेगी, कैमरा कहां रहेगा और दर्शक किस ओर देखेगा, इसकी पहले तैयारी होती है। वे स्वयं मंच–निर्देशक हैं, अभिनेता हैं और सरकार उनकी पटकथा। नौकरशाही प्रोडक्शन टीम और हर बड़ी तारीख एक नया प्रीमियर। सो, अगला सितंबर का शो ब्रिक्स है और सात सितंबर से सात अक्टूबर के बीच देश भर में मोदी की पच्चीस साला सत्ता का भगवा कीर्तन!

युवा अधिवक्ता प्रशांत उपाध्याय चुने गये कार्यकारिणी सदस्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर के सम्पन्न हुये चुनाव में युवा अधिवक्ता प्रशान्त उपाध्याय सदस्य कार्यकारिणी पद पर पर विजयी घोषित हुये। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने श्री उपाध्याय को प्रमाण पत्र दिया। इस पर उपस्थित लोगों ने प्रशांत जी को बधाई देते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। वहीं दीवानी न्यायालय के कार्यकाल में प्रथम ही प्रयास में चुनाव जीतने वाले श्री उपाध्याय ने कहा कि संघ की पवित्रता को देखाते हुये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन किया जायेगा। वहीं जानकारी होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिवेणी नारायण दुबे, तेज बहादुर सिंह, राकेश सिंह, सौरभ सिंह, शशांक दुबे, शशांक सिंह, बृजभूषण शुक्ला, राहुल यादव, रोहित यादव, अर्शी जी, वरिष्ठ पत्रकार अजय पाण्डेय, रामजी जायसवाल, चन्द्र प्रकाश तिवारी सहित तमाम लोगों ने प्रशांत जी को बधाई दिया।

चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले का आरोप, भीम आर्मी ने जांच की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में चंद्रशेखर आजाद के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनके काफिले पर हमले के आरोपों की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान चंद्रशेखर आजाद के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने उनके काफिले पर भी हमला किए जाने का आरोप लगाया। इस संबंध में दिए गए ज्ञापन में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन में घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, पुलिस वायरलेस संदेश, ड्यूटी चार्ट समेत अन्य अभिलेख सुरक्षित कराने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जांच में यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की अभद्रता, अधिकारों के दुरुपयोग अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने तथा चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा, सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मामले की समयबद्ध जांच कर कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की।

सरकार नहीं चाहती ओबीसी की सही आबादी के आंकड़े सामने आएं – संजय माली

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जनगणना–2027 के फॉर्म में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अलग कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संजय माली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को सौंपा। कांग्रेस ने मांग की कि जनगणना फॉर्म में ओबीसी का स्पष्ट कॉलम जोड़ा जाए और जातियों की जानकारी दर्ज करने के लिए पहले से मौजूद जातियों की प्रमाणित सूची अथवा ड्रॉप डाउन सूची उपलब्ध कराई जाए। जिलाध्यक्ष संजय माली ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव–2024 से पहले वर्ष 2027 में ओबीसी वर्ग की जनगणना कराने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 अगस्त 2026 की जनगणना अधिसूचना में ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा गया है। जाति संबंधी जानकारी के लिए ओपन–एंडेड व्यवस्था रखी गई है और पहले से सूचीबद्ध जातियों की ड्रॉप डाउन सूची भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ओपन–एंडेड तरीके से जातियों की गणना करने पर एक ही जाति के नाम अलग–अलग तरीके से दर्ज होने और उसके कई उपनाम अथवा उप–जातियों में बंटने की आशंका रहेगी। इससे ओबीसी की वास्तविक आबादी के साथ उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का सही आकलन करना कठिन होगा। संजय माली ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ओबीसी कॉलम और सूचीबद्ध जातियों की ड्रॉप डाउन सूची शामिल करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और तेलंगाना में जातिगत आंकड़े जुटाने के बेहतर मॉडल मौजूद होने के बावजूद केंद्र सरकार ने जनगणना–2027 में ओबीसी कॉलम नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी जनगणना को स्वीकार नहीं करेगी, जिसमें ओबीसी की वास्तविक संख्या और स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा सामने न आए। पार्टी की मांग है कि ओबीसी आबादी को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, रोजगार और संसाधनों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सही जातिगत आंकड़े जुटाए जाएं।

लखनऊ समेत देशभर में एक दिवसीय बैंक हड़ताल, बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को लखनऊ समेत देशभर में बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक समेत प्रमुख बैंकों की शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक के बाहर बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया।बैंक कर्मी पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण आज बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज नहीं होगा। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी कुछ सेवाएं जारी रहने की संभावना है।बैंक कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। बैंक कर्मियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार और संबंधित पक्षों को गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र समाधान निकालना चाहिए।

चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हर्षोल्लास से मनाया गया हिंदी दिवस

लखनऊ, 14 सितंबर 2026। चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, लखनऊ में हिंदी दिवस समारोह का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की प्रबंध निदेशक श्रीमती ऋतु सिंह ने सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हिंदी भाषा के महत्व और उसके व्यापक प्रयोग पर प्रकाश डाला। प्राचार्या डॉ. अनुराधा त्रिपाठी ने हिंदी दिवस की प्रासंगिकता बताते हुए विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के डॉ. अमरेश कुमार सिंह ने हिंदी दिवस के ऐतिहासिक महत्व, हिंदी की समृद्ध साहित्यिक परंपरा तथा सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में हिंदी की भूमिका पर विस्तारपूर्वक विचार प्रस्तुत किए। समारोह में छात्र–छात्राओं द्वारा नाटक, क्विज प्रतियोगिता, कविता पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी शिक्षक एवं छात्र–छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री विकास दुबे ने किया। समारोह का वातावरण हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान और गौरव की भावना से ओत–प्रोत रहा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी गांव–गांव पहुंचाएंगे पीआरवी वाहन

लखनऊ, (संवाददाता)। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आमजन को जागरूक करने और अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह–समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने संयुक्त रूप से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर से डायल–112 के पीआरवी वाहनों को राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता–3.0 के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की अधिकारी किरण यादव ने वाहनों को रवाना किया।इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी को केवल शहर तक सीमित रखने के बजाय लखनऊ के ग्रामीण, दूरस्थ और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जानकारी के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति लोक अदालत के लाभ से वंचित न रहे। पीआरवी वाहनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे और लोगों को अपने लंबित एवं सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति से सरल, शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार–प्रसार के लिए लखनऊ के नागरिकों को मोटर वाहन अधिनियम के चालानों से संबंधित करीब 19 लाख एसएमएस भी भेजे गए हैं। इन संदेशों के माध्यम से वाहन स्वामियों और आम नागरिकों को 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने सुलहनीय चालानी मामलों के निस्तारण का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया है।

यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त, महिलाएं-बेटियां सुरक्षित - रविंद्र जायसवाल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र कुमार जायसवाल ने रविवार को जौनपुर में पूर्व मंत्री एवं अमर शहीद उमानाथ सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उमानाथ सिंह का राजनीतिक और सामाजिक जीवन बेहद शानदार रहा। उनके बताए मूल्यों और आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि आज की राजनीति में उमानाथ सिंह जैसे मूल्यों और आदर्शों की कमी महसूस होती है। उनके जीवन से समाज और राजनीति में सकारात्मक योगदान की प्रेरणा मिलती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर संतोष जताते हुए जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक चल रही है। महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं रात 11 बजे भी बाजार या अपना काम निपटाकर सुरक्षित घर लौट रही हैं। कानून व्यवस्था बेहतर होने का सबसे बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। जौनपुर में हाल में हुई हत्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के सवाल उठाने पर मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि कहीं हत्या हो रही है तो अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। आज हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और उन्हें कानून के शिकंजे से बचने का मौका नहीं मिलता।

लंगूर बंदरों के आतंक से मिली राहत, मनोज चौधरी ने पकड़वाकर वन विभाग को सौंपा

लखनऊ, (संवाददाता)। रुधौली विकासखंड क्षेत्र के सुरवार, रमवापुर, बिजहरडूहा, टिकरी, ढोढऊपार सहित दर्जनों गांवों में लंगूर बंदरों के आतंक से ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे। बंदरों के झुंड से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार, बंदरों के हमले में करीब 20 लोग घायल भी हो चुके हैं।बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान ग्रामीणों ने इसकी सूचना रुधौली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी मनोज चौधरी को दी। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मिलते ही मनोज चौधरी ने तत्काल बंदर पकड़ने वाली टीम को बुलवाया। टीम ने अभियान चलाकर आतंक का कारण बने लंगूर बंदरों को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें संबंधित विभाग को सौंप दिया गया।समाजसेवी मनोज चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से उन्हें लगातार बंदरों के आतंक की सूचना मिल रही थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने तत्काल पहल करते हुए बंदरों को पकड़वाने की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा कि लंगूर भी जीव हैं, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों में उनके रहने से ग्रामीणों को परेशानी और खतरा पैदा हो रहा था। अब संबंधित विभाग इन्हें उनके अनुकूल सुरक्षित स्थान और जंगल क्षेत्र में पहुंचाने की कार्रवाई करेगा। लंगूर बंदरों के पकड़े जाने के बाद प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए मनोज चौधरी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए समय पर की गई इस पहल से उन्हें काफी राहत मिली है।

छह माह पुराने लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण करें - एडीजी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 14 सितंबर। अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन नवीन अरोड़ा ने सोमवार को पुलिस कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर जनसुनवाई की तथा अधिकारियों के साथ बैठक में कानून–व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को छह माह पुराने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान एडीजी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक स्तर पर मामलों का निस्तारण ठीक हो रहा है, लेकिन अधीनस्थ स्तर पर कुछ मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं है। एसआई स्तर पर लंबित पत्रावलियों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं से संबंधित आर्थिक शोषण के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे भेजने के निर्देश दिए। पुराने लूट, डकैती और हत्या के मामलों की भी समीक्षा करते हुए उनके जल्द खुलासे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। हिस्ट्रीशीटरों की आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और लगातार निगरानी के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में दोनों पक्ष आमने–सामने होते हैं। पुलिस की प्राथमिकता सही व्यक्ति के साथ न्याय करना है। सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है और किसी को संतुष्ट करने के लिए गलत कार्रवाई नहीं की जा सकती। गैंग बनाकर घटनाओं को अंजाम देने वालों तथा गैंग तैयार करने वालों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्व संबंधी मामलों पर उन्होंने कहा कि इनके निस्तारण के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को समन्वय से संयुक्त टीम बनानी चाहिए, ताकि मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके। शहर की यातायात व्यवस्था पर एडीजी ने कहा कि जाम से निपटना केवल ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। सिविल पुलिस भी अपने क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ट्रैफिक पुलिस सहयोग के लिए है और उसकी संख्या इतनी नहीं है कि हर स्थान पर तैनाती की जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कार्यालय के कार्य की तुलना में अधिक कर्मचारियों की तैनाती पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कार्यभार के अनुसार मानव संसाधन के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। इसके अलावा कार्यालय की विभिन्न शाखाओं, अभिलेखों और पत्रावलियों का निरीक्षण कर साफ–सफाई एवं कार्यों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।

छात्रवृत्ति का लाभ हर पात्र विद्यार्थी तक पहुंचाना प्राथमिकता – जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (पीयू) एवं जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में 'छात्रवृत्ति योजना का सफल क्रियान्वयन' विषयक एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी पात्र छात्र–छात्रा को जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रिया संबंधी कठिनाई के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से आवेदन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति वितरण के मामले में जौनपुर पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग आसान बनाती है। उन्होंने प्रत्येक शिक्षण संस्थान में 'छात्रवृत्ति पटल' स्थापित करने का सुझाव दिया, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके। जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने विभागों और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी। कार्यशाला में महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्रबंधक और कर्मचारियों ने छात्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न उठाए, जिनका अधिकारियों ने समाधान बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। संचालन सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. नितेश जायसवाल ने किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी, उपकुलसचिव अजीत प्रताप सिंह सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी मौजूद रहे।

मिर्जापुर में 3.28 करोड़ रुपये से बनेगा बचपन डे केयर सेंटर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगजन कल्याण एवं विकास तथा उनके सुगम पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनपद मिर्जापुर में 'बचपन डे केयर सेंटर' के भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मूल्यांकन समिति की संस्तुति के आधार पर परियोजना की कुल लागत 328.42 लाख रुपये यानी करीब 3.28 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के अंतर्गत निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए पहली किस्त के रूप में 200 लाख रुपये यानी दो करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।सरकार के अनुसार भवन निर्माण का कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

एंबुलेंस के इंतजार में स्ट्रेचर पर तड़पता रहा घायल, जिला अस्पताल पहुंचते ही मौत

गोरखपुर, (संवाददाता)। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए 65 वर्षीय व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा से जिला अस्पताल रेफर किए जाने के बाद एंबुलेंस के लिए करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। परिजन 108 नंबर पर लगातार फोन करते रहे लेकिन उन्हें जल्द एंबुलेंस पहुंचने का आश्वासन ही मिलता रहा। काफी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर परिजनों ने निजी वाहन से मरीज को ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच एंबुलेंस पहुंची और मरीज को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, उरुवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी राजकुमार गुप्ता शुक्रवार दोपहर छत से गिर गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। परिजन आनन–फानन में उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों ने 108 नंबर पर एंबुलेंस के लिए फोन किया। आरोप है कि फोन उठाने के बाद उन्हें लगातार यही बताया जाता रहा कि एंबुलेंस उनके पास पहुंच रही है। काफी समय बीतने के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए। उन्होंने निजी वाहन की व्यवस्था के लिए भी फोन करना शुरू कर दिया। इस दौरान मरीज पीएचसी परिसर में स्ट्रेचर पर तड़पता रहा। स्थिति को देखते हुए परिजनों ने मौके पर मौजूद चिकित्सक से मदद मांगी। चिकित्सक ने बेलघाट से एंबुलेंस की व्यवस्था कराने के लिए फोन किया। कुछ देर बाद एंबुलेंस पीएचसी पहुंची और परिजन राजकुमार को लेकर जिला अस्पताल रवाना हुए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. जेपी त्रिपाठी ने बताया कि लगभग 2रू30 बजे मरीज आया था। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने रेफर किया। उस समय यहां की एंबुलेंस जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गई थी। जिला मुख्यालय पर बात करने के बाद बेलघाट की गाड़ी भेजी गई।

एजुकेशन लोन से आसान होगी उच्च शिक्षा की राह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान में सोमवार को विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन की सुविधाओं और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा जौनपुर के सौजन्य से हुआ। कार्यशाला में बैंक के प्रशांत ओझा एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, ऋण स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक संसाधनों की कमी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा न बने, इसके लिए बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बैंक प्रतिनिधियों ने आवेदन से जुड़ी औपचारिकताओं को सरल भाषा में समझाया। विद्यार्थियों ने एजुकेशन लोन से संबंधित विभिन्न सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से जवाब दिया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध वित्तीय विकल्पों के प्रति जागरूक करना और जरूरत पड़ने पर शिक्षा ऋण का लाभ लेने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना रहा। इस अवसर पर फार्मेसी संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉ. नृपेन्द्र सिंह, प्रो. नरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. शक्ति जायसवाल, मिथिलेश चौरसिया सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। संस्थान की ओर से बैंक अधिकारियों एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कला उत्सव में एमपीएलएल आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

अयोध्या।कला उत्सव जनपद स्तरीय प्रतियोगिता–2026 में एमपीएलएल आदर्श इंटर कॉलेज,अयोध्या के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया।विभिन्न विधाओं में प्रतिभाग करते हुए छात्रों ने दो प्रतियोगिताओं में प्रथम तथा चार में द्वितीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।शास्त्रीय नृत्य एकल प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र देव निषाद ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया।जबकि पारंपरिक कहानी वाचन समूह में आकार निषाद एवं अंशुमान ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोनों ही छात्र अब मंडल स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।पारंपरिक लोकगीत प्रतियोगिता में यश जायसवाल, देवांश जायसवाल, प्रिंस कुमार गौतम एवं जयवर्धन साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया। पारंपरिक लोक नृत्य में दिव्यांश कनौजिया, यश साहू एवं प्रिंस मौर्य ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।इसके अलावा अवनद्ध वाद्य एकल प्रतियोगिता में अभिषेक विश्वकर्मा ने सिल्वर मेडल हासिल किया।प्रतियोगिता में सफलता के बाद विद्यालय में आयोजित प्रार्थना स्थल पर सभी विजेता छात्रों को ट्रॉफी, मेडल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे।कला उत्सव की तैयारियों एवं छात्रों के मार्गदर्शन में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता मौजी लाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय के प्रबंधक आलोक कुमार अग्रवाल ने छात्रों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।प्रधानाचार्य बरुण प्रताप सिंह ने भी सभी विजेता छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

तीन महिला एसआई को चौकी प्रभारी की कमान मिलने से अयोध्या पुलिस में दिखी महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर

अयोध्या।अयोध्या पुलिस में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम बदलाव देखने को मिला है।एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने पिछले दिनों तीन महिला उप निरीक्षकों को जिले की अलग–अलग पुलिस चौकियों की जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें सीधे क्षेत्रीय पुलिसिंग में नेतृत्व का अवसर दिया है।एक साथ तीन महिला उप निरीक्षकों को चौकी प्रभारी बनाए जाने से पुलिस महकमे में महिला नेतृत्व को लेकर नई तस्वीर सामने आई है।एसएसपी डाक्टर गौरव ग्रोवर ने कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक किरन पाल को थाना कैंट की मीरानघाट चौकी, थाना रुदौली में तैनात उप निरीक्षक स्तुति गुप्ता को ऐहार चौकी तथा थाना पटरंगा में तैनात उप निरीक्षक प्रतीक्षा को दिवाली चौकी का प्रभारी बनाया गया है।चौकी प्रभारी के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने से इन महिला उप निरीक्षकों को क्षेत्र में कानून–व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और आमजन की समस्याओं से सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिलेगा।बताते चले कि महिला पुलिस कर्मियों को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने की दिशा में वर्ष 2023 में भी प्रदेश स्तर पर जोर दिया गया था।मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिला पुलिस अधिकारियों को केवल महिला थानों तक सीमित न रखते हुए उन्हें पुरुष थानों और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने पर बल दिया गया था।इसी क्रम में उस समय अयोध्या जिले में आशा शुक्ला को थाना मवई की प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी।यह नियुक्ति जिले में महिला पुलिस अधिकारी को सामान्य थाना संचालन की जिम्मेदारी दिए जाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी गई थी।हालांकि बाद में उनका स्थानांतरण कर दिया गया।एक बार फिर चौकी प्रभारी के रूप में एक साथ तीन महिला उप निरीक्षकों को जिम्मेदारी मिलना निश्चित रूप से महिला पुलिसकर्मियों के लिए नेतृत्व के नए अवसर का संकेत है। देखा जाए तो आने वाले दिनों में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर महिला निरीक्षक व महिला उप निरीक्षक को जिले के किसी थाना पर थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक के रूप में भी तैनात कर सकते हैं।चौकी प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिलने के बाद इन महिला उप निरीक्षकों के सामने क्षेत्र में कानून–व्यवस्था बनाए रखने,अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, पीड़ितों की सुनवाई, महिला सुरक्षा तथा आमजन से बेहतर समन्वय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहेंगी।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ी, सोनौली बॉर्डर पर हाई अलर्ट, संघन जांच अभियान शुरू

गोरखपुर, (संवाददाता)। दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर भारत–नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनौली बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने सघन जांच अभियान शुरू किया है। नेपाल से भारत आने वाले लोगों और उनके सामान की गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। डॉग स्क्वायड और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। खुली सीमा को देखते हुए मुख्य सीमा के साथ पगडंडियों और संवेदनशील स्थानों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। सीओ नौतनवा बसंत कुमार सिंह ने बताया कि एसएसबी के साथ संयुक्त निगरानी और जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।

अयोध्या घूमने निकलीं दो छात्राएं, अपहरण का शक हुआ झूठा

गोरखपुर, (संवाददाता)। घरवालों से अयोध्या घूमने की अनुमति नहीं मिलने की आशंका में कक्षा नौ और 11 की दो छात्राएं बृहस्पतिवार को बिना बताए निकल गईं। देर शाम तक घर नहीं पहुंचीं और गांव की पक्की सड़क पर उनकी साइकिल व स्कूल बैग मिले तो परिजनों को अपहरण का शक हुआ। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की। शुक्रवार सुबह दोनों अयोध्या रेलवे स्टेशन पर सकुशल मिल गईं। पिपराइच थाना क्षेत्र के अतरवलिया गांव की दोनों छात्राएं भटहट कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ती हैं। दोनों रोजाना साथ में साइकिल से स्कूल जाती हैं। बृहस्पतिवार को भी दोनों स्कूल गई थीं।

महिला की मौत के मामले में बस चालक पर प्राथमिकी, चालक की तलाश

गोरखपुर, (संवाददाता)। शिवपुर टोला (विन्टोलिया) में वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल की बस की चपेट में आने से महिला की मौत के मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तहरीर में चालक पर तेज गति और लापरवाही से बस चलाने तथा गलत दिशा में आकर महिला को टक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। पुलिस बस के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उनकी ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच कर रही है। कागजात में कमी मिलने पर संबंधित धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। शिवपुर टोला निवासी निर्देश की पत्नी आरती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी सास माधुरी देवी (55) बृहस्पतिवार दोपहर परागी देवी और राजमती देवी के साथ राशन लेकर घर लौट रही थीं। करीब 2रू10 बजे चकदहा मोड़ के पास सामने से आ रही स्कूल बस ने गलत दिशा में आकर माधुरी को टक्कर मार दी। आरोप है कि बस चालक वाहन तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। टक्कर लगने से माधुरी सड़क पर गिर गईं। तहरीर के मुताबिक, चालक बस लेकर भागने लगा और इसी दौरान बस का पिछला पहिया माधुरी के ऊपर चढ़ गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। गांव के लक्ष्मण ने डायल 112 पर सूचना दी थी। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बस के ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

खबर छपने के बाद हरकत में आया नगर निगम,डायट आने जाने वाले लोगों को मिली कूड़े के ढेर से मुक्ति

अयोध्या।शहर के डायट मुख्य गेट पर व्याप्त गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है।खबर में जिस स्थान पर लंबे समय से कूड़े का ढेर और उससे फैल रही दुर्गंध की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था।वहां नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए सफाई कराई।अब कूड़े के ढेर की जगह साफ–सफाई दिखाई दे रही है।नगर निगम की इस कार्रवाई से उक्त मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों के साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट),अयोध्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है।सफाई होने के बाद यहां का वातावरण पहले की अपेक्षा काफी बेहतर नजर आ रहा है।डायट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों ने नगर निगम की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पहले इस स्थान से गुजरते समय कूड़े के ढेर के कारण काफी दुर्गंध का सामना करना पड़ता था।कई बार वहां से निकलना भी मुश्किल लगता था,लेकिन अब सफाई होने से काफी राहत मिली है।वहीं प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों ने भी सफाई व्यवस्था में हुए सुधार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास स्वच्छ वातावरण होना बेहद जरूरी है। कूड़ा हटने और सफाई होने से न केवल दुर्गंध की समस्या कम हुई है, बल्कि आसपास का माहौल भी बेहतर हुआ है।स्थानीय लोगों और राहगीरों ने भी नगर निगम की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ताकि दोबारा कूड़े का ढेर न लग सके।

पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री की पत्नी बीना खत्री का निधन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।फैजाबाद के पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री की धर्मपत्नी बीना खत्री का सोमवार को निधन हो गया।उनके निधन पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर एक शोक सभा आयोजित की गई।जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने किया तथा संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने किया।बैठक में उपस्थित कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर बीना खत्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया।श्री पाठक ने बताया वह लखनऊ में अपने बेटे के पास रह रही थी और मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।कैंसर पीड़ित बीना का काफी समय से इलाज चल रहा था।मालूम हो कि बीना जी वरिष्ठ पत्रकार हरि कृष्ण अरोड़ा की बहन हैं।ईश्वर बीना जी की आत्मा को शांति और निर्मल जी के परिवार को यह पहाड़ जैसा दुःख सहन करने की शक्ति दे।बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम,कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह,रामदास वर्मा, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, महेश वर्मा,कबिन्द्र साहनी, सेवादल जिला अध्यक्ष फ्लावर नकवी दानिश जिया मंसाराम यादव राम अवध पासी, धर्मेंद्र सिंह फास्टर अशोक राय सुरेंद्र सिंह सैनिक राजकुमार पांडे आदि प्रमुख लोग रहे

1200 सीटों पर आज से मॉपअप राउंड, न पहुंचने पर खाली कराई जा रहीं सीटें

वाराणसी, (संवाददाता)। बीएचयू में स्नातक, परास्नातक और बीए–बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए मॉपअप राउंड शुरू हो गया है। यूजी की करीब 1200 सीटों पर शनिवार से ऑनलाइन मॉपअप राउंड शुरू होगा। जल्द ही फीस भुगतान करने का लिंक जारी कर दिया जाएगा। वहीं, बीए–बीएड में प्रवेश पाने के लिए 15 सितंबर तक मौका है। यदि 15 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच परिसर में नहीं पहुंचे तो बीए–बीएड में दाखिला नहीं मिलेगा। पीजी की खाली सीटों का विवरण केंद्रीय प्रवेश समिति की ओर से समर्थ पोर्टल को भेज दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी रिपोर्टिंग के लिए परिसर में नहीं पहुंचे, उनकी सीटें खाली कराई जा रही हैं। वहीं, पीजी में अभी अंतिम मॉपअप राउंड में दाखिला चल रहा है। केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि सीयूईटी दे चुके उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है, जो अभी तक कहीं प्रवेश पाने में सफल नहीं हुए हैं। मॉपअप के पहले राउंड का सीट आवंटन 15 सितंबर को स्टूडेंट पोर्टल पर घोषित होगा। इसके लिए फीस भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। बीपीए और बीएफए कोर्स के लिए पहले दौर का सीट आवंटन 16 सितंबर को होगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। दूसरे चरण के सीट आवंटन की घोषणा 18 सितंबर को समर्थ पोर्टल पर होगी।

21 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने सीखा एफएलसी का प्रोटोकॉल, हुआ मूल्यांकन

वाराणसी, (संवाददाता)। ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की प्रक्रिया को कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में 21 जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी से जुड़े कार्मिकों को तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर अधिकारियों को ईवीएम–वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच की तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपायों और निर्धारित प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, विशिष्ट अतिथि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अखंड प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव भारत निर्वाचन आयोग बीसी पात्रा, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अमित सिंह एवं अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग राकेश कुमार ने किया। कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सावधानियों की जानकारी दी। ईवीएम पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सुरक्षा उपायों, एफएलसी की प्रक्रिया तथा विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों की भूमिका के संबंध में प्रस्तुतियां दी गईं। विशेषज्ञों ने ईवीएम एवं वीवीपैट के संपूर्ण जीवन चक्र के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया। इसमें मशीनों के संचालन, रैंडमाइजेशन, कमीशनिंग, मतदान प्रक्रिया, मतगणना तथा मतगणना के बाद की प्रक्रियाओं सहित विभिन्न प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई। कार्यशाला में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, गोंडा, संत कबीरनगर, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एफएलसी सुपरवाइजर ने हिस्सा लिया। बीईएल के विशेषज्ञ इंजीनियर रवि रंजन, राहुल कुशवाहा एवं रामा मीनन कुमार डी ने ईवीएम एवं वीवीपैट की तकनीकी संरचना और सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

टॉवर पर चढ़ने वाले युवक का शांति भंग में चालान

गोरखपुर, (संवाददाता)। शादीशुदा महिला पर लगातार शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए गुलरिहा थाना क्षेत्र के डुमरी नंबर दो रुषापुर टोला निवासी सूरज चौहान बृहस्पतिवार शाम गांव के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। पुलिस ने समझाकर उसे नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। शुक्रवार को उसका शांति भंग में चालान कर दिया। सूरज के मुताबिक, करीब नौ महीने पहले महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र की एक महिला से उसकी फोन पर बातचीत शुरू हुई थी।

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने आजमगढ़ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू कीं

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

आजमगढ़। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने आजमगढ़ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के शुरू होने से आजमगढ़ और आसपास के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह अब अपने शहर के करीब मिल सकेगी। इस ओपीडी सेवा में मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के एसोसिएट कंसल्टेंट – डॉ. साई किरण, मरीजों को परामर्श देंगे। डॉ. साई किरण हर महीने के दूसरे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सरोज मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिधारी, आजमगढ़ में उपलब्ध रहेंगे। मरीज यहां डॉक्टर से सलाह लेने और इलाज के बाद फॉलो–अप के लिए उनसे मिल सकेंगे। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के एसोसिएट कंसल्टेंट – डॉ. साई किरण ने कहा, "कैंसर का समय पर पता लगना उसके सफल इलाज में सबसे अहम भूमिका निभाता है और इससे मरीज के बेहतर इलाज की संभावना बढ़ती है। कैंसर को लेकर बढ़ती जागरूकता और इलाज के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण अब मरीजों के लिए पहले से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं। इस ओपीडी के जरिए आजमगढ़ और आसपास के इलाकों के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

जनता दरबार मे समस्या का समाधान करते हुए दिव्यांग को तत्काल उपलब्ध कराई ट्राई साइकिल

अयोध्या।जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनने के दौरान उस समय मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल देखने को मिली,जब मिल्कीपुर विकासखंड के ग्राम सभा जोरियम निवासी पवन कुमार पुत्र विजय बहादुर पाण्डेय अपनी समस्या लेकर पहुंचे।उनकी स्थिति देखकर सीडीओ केके सिंह ने तत्काल उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए समाधान किया।इस मौके पर सीडीओ श्री सिंह के निर्देश पर वहाँ पर मौजूद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने दिव्यांग पवन कुमार को तत्काल ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई।अचानक मिली इस मदद से पवन कुमार के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठी।उन्होंने अधिकारियों के प्रति आभार जताया। जनता दर्शन में मौजूद लोगों ने भी सीडीओ की इस संवेदनशील पहल की सराहना की।

परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि फिर बढ़ी, अब 30 तक भरें

भदोही, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए छात्र–छात्राओं को बड़ी राहत दी है। परिषद ने एक बार फिर पंजीकरण और फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी। पहले अंतिम तारीख 10 सितंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि कक्षा 9 और 11 के छात्र अब 30 सितंबर की रात 12 बजे तक अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा करके बोर्ड की वेबसाइट नचउेच.मकन.पद पर ऑनलाइन जानकारी अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद प्रधानाचार्य वेबसाइट से चेकलिस्ट लेकर छात्र–छात्राओं की जानकारी की जांच एक से चार अक्तूबर तक करेंगे। पंजीकृत छात्रों की फोटो वाली लिस्ट जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 15 अक्तूबर तक जमा करनी होगी। परीक्षा 2027 के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए, स्कूल के प्रधानाध्यापक सभी योग्य छात्र–छात्राओं का परीक्षा शुल्क एक साथ चालान से सरकारी खजाने में 28 सितंबर जमा कराएंगे। सरकारी खजाने में जमा शुल्क की जानकारी और पढ़ाई से जुड़ी डिटेल नचउेच.मकन.पद पर 30 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। वेबसाइट से चेकलिस्ट लेकर जानकारी की जांच और बदलाव एक से छह अक्तूबर तक किया जा सकेगा। 15 अक्तूबर तक डीआईओएस कार्यालय में जमा करना होगा।

आईजीआरएस पोर्टल पर गलत और भ्रामक आख्या देने से बचें अफसर

भदोही, (संवाददाता)। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह ने बताया कि श्रेणी सी के संदर्भों को संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा गलत आख्या स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रकरण में तथ्य छिपाने या गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आईजीआरएस से संबंधित नवीनतम शासनादेशों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां निरीक्षण करने जाए तो फोटो और दो गवाहों का सिग्नेचर भी कराए। डीएम ने विशेष रूप से उन गावों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए, जहां शिकायतों की संख्या अधिक है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।